(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा भविष्य में देश में राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन की औसत दर को बढ़ाने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) सन् 2000-2001 के लिए देश में दुग्ध उत्पादन के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

(ग) जी, नहीं । इस समय राष्ट्रीय स्तर पर प्रति पशु प्रति दिन औसत उत्पादकता है : गाय 2.19 कि० ग्रा० तथा भैंस 3.59 कि० ग्रा० ।

(घ) और (ङ) दूध का मूल्य विभिन्न आर्थिक तथा गैर-आर्थिक कारणों जैसे दुग्ध-उत्पादन की आदान लागत सामान्य अर्थव्यवस्था की स्थिति, दूध की खपत, बाजार का रूझान, फार्म उद्यमों पर प्रतिस्पर्धा की लाभदायकता आदि पर निर्भर करता है । दूध की खपत आमदनी के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है तथा निचले स्तरों पर यह पौषणिक आवश्यकता से भी कम होती है । गरीबी रेखा से नीचे के लोगो के पौषणिक स्तर मे वृद्धि करने के लिए विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ किए गए है । देश में प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता की औसत दर के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं । तथापि, वर्ष 1996-97 (8वी परियोजना का अंतिम वर्ष) के लिए दुग्ध उत्पादकता का लक्ष्य 70.78 मिलियन टन निर्धारित किया गया है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठन द्वारा कृषि फार्मों की स्थापना किया जाना

2758. **श्रीमती सुषमा स्वराज्य :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ मिलकर बड़े-बड़े कृषि फार्मों की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विगत महीनों के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इस प्रकार के सफल प्रयास किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और क्या सरकार द्वारा इस तरह के बड़े-बड़े कृषि फार्मों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की कोई नीति भी अपनायी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

ड्रिप और स्प्रिकल सिंचाई परियोजना को प्रोत्साहन दिया जाना

2759. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में जल का समुचित उपयोग करने हेतु कृषि क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिकल सिंचाई परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने देश मे ड्रिप और स्प्रिकल सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु क्या-क्या सुविधायें प्रदान करने का निर्णय किया है; और

(ग) सरकार ने ये सभी सुविधायें कृषकों तक पहुंचाने हेतु क्या प्रणाली अपनायी है और इस प्रणाली का वर्तमान में देश के किन-किन क्षेत्रों में अधिक उपयोगी होने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हा ।

(ख) तिलहनों, दलहनों और कपास-फसलों में ऑयल पाम और स्प्रिंकलर प्रणालियों सहित, बागवानी-फसलों में ड्रिप प्रणाली के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी समर्थन मुहैया करा रही है ।

(ग) सरकार इन फसलों को उगाने वाले संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों के माध्यम से उपरोक्त योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है । संभवत: ये प्रणालिया शुष्क भूमि/निर्जल क्षेत्रों में और अधिक लाभदायक होंगी ।

गन्ने का कम उत्पादन

2760. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष पूरे देश में गन्ने का उत्पादन बहुत कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) गन्ने की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि के दौरान 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में "गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास" की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ।

मछली पकड़ने वाले पुराने जलयान

2761. **श्री आस मोहम्मद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में मछली पकड़ने वाले जलयान बहुत पुराने हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार ने मछली पकड़ने वाले आधुनिक जलयान प्राप्त करने हेतु अभी तक क्या प्रयास किये है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1992-93 के अन्त तक देश में मछली पकड़ने वाले 25,500 यंत्रीकृत जलयान, मछली पकड़ने वाली 25,500 मोटर लगी नौकायें तथा 1,72,000 पारम्परिक (गैर-यंत्रीकृत) नौकाये थी। इसके अतिरिक्त, संयुक्त उद्यमों / पट्ट की व्यवस्थाओं के अंतर्गत वर्तमान में वास्तविक रूप से प्रचालन में 19 जलयानों के अलावा गहरे समुद्र में झींगा पकड़ने वाले लगभग 180 जलपोत संचालित किए जा रहे थे। सरकार की नीति पारम्परिक नौकाओं के यंत्रीकरण मोटरीकरण को प्रोत्साहन देने की रही है जिससे अधिक दूर तक समुद्री यात्रा की क्षमता बढती है तथा परिणामस्वरूप मछवारे अधिक मछली पकड़ते है और उनकी अधिक आय होती है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को प्रोत्साहन देने की नीति है ताकि गहरे समुद्र के मत्स्यन संसाधकों का, देश में समुद्रीय मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने में प्रयोग किया जा सके जो कि इस समय किसी महत्वपूर्ण सीमा तक उपयोग में नहीं लाए जा रहे है ।

(ग) सरकार द्वारा समुद्रीय मत्स्यन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए उठाये गये कुछ बड़े कदमों में संचालन के क्षेत्र का विस्तार 50 मीटर की गहराई से अधिक तक करने के लिए मछली पकड़ने वाली पारम्परिक नौका का मोटरीकरण, शार्क, ट्रूना आदि के लिए बहु-अवसर मध्यवर्ती किस्म के समुद्र-तट से दूर मछली पकड़ने वाली जलयानों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना; द्विपक्षीय तौर पर सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत समुद्र तट से दूर मछली पकड़ने के आधुनिक जलयानों का अधिग्रहण; संयुक्त उद्यम/विदेशी मत्स्यन जलयानों के पट्ट के अंतर्गत परिष्कृत इलैक्ट्रानिक तथा मत्स्यन औजारों के साथ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों के प्रवेश को प्रोत्साहन देना; विविध तथा विशिष्ट मात्स्यिकी संसाधन के संचालन के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विद्यमान जलयानों में सुधार करना, इत्यादि शामिल है ।

बटर ऑयल का आयात

2762. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बटर ऑयल का आयात कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो आयात किए जाने के क्या कारण है तथा आयात के लिए प्राधिकृत की गई एजेंसी का नाम क्या है, और उस देश का नाम क्या है जिसके साथ बटर ऑयल के आयात के लिए सौदा किया गया है ;

(ग) आयातित बटर आयल की कुल मात्रा कितनी है ; और

(घ) इसके आयात पर कुल कितना खर्च होगा और किस समय तक और किस मूल्य पर आम जनता को इस आयातित बटर ऑयल को उपलब्ध कराया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) देश में मुख्य रूप से दुग्ध वसा की कमी पर काबू पाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को चालू वित्त वर्ष के दौरान बटर ऑयल का आयात करने की अनुमति दी है । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने बटर ऑयल का आयात करने के लिए न्यूजीलैण्ड तथा आस्ट्रेलिया की पार्टियों से संपर्क किया है ।

(ग) और (घ) वर्ष के दौरान अब तक आयात किए गए बटर ऑयल की मात्रा इस प्रकार है :—

महीना	प्राप्त/प्राप्त की जा रही मात्रा	लागत (मी० टन) (अमरीकी डॉलर)
अक्तुबर, 94	250 मी० टन	1600 लागत तथा भाडा
नवम्बर, 94	(क) 250 मी० टन	1600 लागत तथा भाडा
	(ख) 992 मी० टन	1730 लागत सहित भाडा
दिसम्बर, 94	1008 मी० टन	1730 लागत सहित भाडा
	800 मी० टन	1730 लागत सहित भाडा